Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
3 फरवरी 2020

बदनाम करने और निशाना बनाने के नए सिलसिले के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद का लोकतांत्रिक एवं कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कालीकट में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव में भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ जनता को जागरूक करने के साथ–साथ मीडिया द्वारा संगठन को बदनाम करने और पुलिस द्वारा कानून व अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कानूनी लड़ाई को तेज़ करने का फैसला किया है। बैठक में कुछ मीडिया के द्वारा संगठन को बदनाम करने के नए सिलसिले और बीजेपी शासित राज्य विशेषकर यूपी में पुलिस के अत्याचार की कड़ी निंदा की गई।

भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन कानून की वजह से भड़के लोगों के गुस्से और प्रदर्शनों के बाद कुछ कठपुतली मीडिया ने कुछ केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर अजीबोगरीब और बेतुके आरोप लगाते हुए, बड़े पैमाने पर संगठन के खिलाफ गलतफहमियां फैलाने का अभियान शुरू कर दिया है। देश की जनता के सामने अलग–अलग एजेंसियों का हवाला देकर आए दिन नई–नई खबरें, लेख और ब्रेकिंग न्यूज़ पेश की जा रही हैं। हालांकि कोई भी एजेंसी अब तक संगठन के खिलाफ किसी भी देश–विरोधी गतिविधि को साबित कर नहीं कर पाई है। शुरू में पॉपुलर फ्रंट पर यह आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में सीएए–विरोधी प्रदर्शनों में हुई हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट का हाथ है। उसके बाद आरोप इस तरफ मोड़ दिया गया कि देश भर में हो रहे सीएए–विरोधी प्रदर्शनों को फंडिंग पॉपुलर फ्रंट कर रहा है। मौजूदा अभियान के पीछे इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है कि सीएए–एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के साथ–साथ पॉपुलर फ्रंट को भी कमज़ोर और बदनाम किया जाए जो आरएसएस–बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ हमेशा मज़बूती से खड़ा रहा है। बैठक में याद दिलाते हुए कहा कि इन अहंकारी हरकतों से न तो जन–प्रदर्शनों को पराजित किया जा सकता है और न ही पॉपुलर फ्रंट को दबाया जा सकता है।

दिल्ली में हिंदुत्व जुनूनी गुंडों को खुली छूट

दूसरे प्रस्ताव में बैठक ने कहा कि दिल्ली और बीजेपी शासित राज्यों में जन विरोधी कानून सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को भयभीत करने और डराने की कोशिशें की जा रही हैं। देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती के बावजूद ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां हिंदुत्व जुनूनी गुंडे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं और दूसरी हिंसक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। जामिया नगर गोलीकांड के समय पुलिस के पास हमलावर को धर दबोचने और उससे हथियार छीन लेने का पूरा अवसर था। लेकिन फिर भी उसे खुली छूट दी गई, जिसके कारण एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच हिंदुत्व नेताओं ने इस प्रकार की हिंसक हरकतों को दूसरे शब्दों में समर्थन करना जारी रखा और केवल 2 दिनों के अंदर ही गोली चलाए जाने की दूसरी घटना सामने आई और क्षेत्र में कुछ बंदूक से लैस लोगों को पाया गया। ऐसे अपराधियों को माफी देना और हिंदुत्व समूह और नेताओं की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत करना साफ तौर पर दूसरे लोगों को भी उनके रास्ते पर चलने के लिए उभारता है। वे लोगों को जमा कर रहे हैं और शाहीन बाग और जामिया नगर में शांतिपूर्ण तरीके से

प्रदर्शन कर रहे लोगों को बच्चों और महिलाओं पर हमला करने की धमकियां दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ''आतंकवादियों के लिए गोली'' वाले बयान को इस प्रकार के हमलों के लिए लोगों को भड़काने से जोड़ा जा सकता है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है। जिस राजनीतिक संकट से बीजेपी और आरएसएस कानूनी तरीकों से नहीं निकल पा रही हैं, उस पर जीत हासिल करने के लिए एक प्रकार की अंडरवल्ड सरकार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ने खबरदार करते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग को पूरा नहीं करती, यह संकट खत्म होने वाला नहीं है।

यूपी में गैरकानूनी गिरफ्तारियां और पुलिस का अत्याचार बंद करो

एक अन्य प्रस्ताव में बैठक ने उत्तर प्रदेश में अभी भी जारी गैर–क़ानूनी गिरफ्तारियों और पुलिस द्वारा लोगों को परेशान किए जाने की निंदा की। देश के मौजूदा इतिहास में, यूपी के अंदर पुलिस के अत्याचार की सबसे बुरी सूरत देखने को मिली है। कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, युवाओं की एक बड़ी संख्या को उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, करोड़ों की संपत्ति को तहस–नहस कर दिया गया और निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। पॉपुलर फ्रंट जैसे संगठन को बदनाम किया गया और उसके नेताओं को कथित सीएए–विरोधी हिंसा के ''मास्टरमाइंड'' के रूप में पेश किया गया। लेकिन सबूत न मिलने पर उनमें से अधिकतर को ज़मानत पर जेल से रिहा कर दिया गया है। अब राज्य से फिर ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने निर्दोषों को परेशान और गिरफ्तार करने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। जिन लोगों को ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, पुलिस उन्हें तलाश करके फिर से हिरासत में ले रही है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पुलिस उनके घर जाकर उनके परिवार वालों को परेशान कर रही है और फर्ज़ी मुकदमों में फंसा रही है। पॉपुलर फ्रंट राजनीतिक पार्टियों और नागरिको और समाजिक समूहों से अपील करता है कि वे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पुलिस राज के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें।

एम. मोहम्मद अली जिन्ना

महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली